साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 01-07 नवंबर 2021, वर्ष-7, अंक-31

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे

हमारे सभी बड़े पर्व-त्योहार किसान और किसानी से जुड़े हुए हैं। दीपावली धन-धान्य का त्योहार है। वैसे तो भगवान श्रीराम रावण को मारकर जिस दिन अयोध्या वापस आए थे, उस दिन से दीपावली महापर्व मनाने की शुरुआत हुई थी, लेकिन समय-चक्र को देखें तो यह वह समय होता है, जब खरीफकी फसल पककर किसानों के घर में पहुंच चुकी होती है। यही अनाज यानी धान्य किसानों के घर में धन का भंडार बन जाता है। तब, आभार जताने के लिए किसान लक्ष्मी मैया और भगवान गणेशजी का पूजन करते हैं। धन और धान्य की जरूरत केवल किसानों को ही नहीं होती, समाज के सभी वर्गों को इसकी जरूरत होती है। लिहाजा दीपावली सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व बन गई है। ऐसा इसलिए भी हुआ कि यह पर्वों का एक पूरा का पूरा गुलदस्ता है। उत्सव धनतेरस से शुरू होता है और भाईदूज तक चलता रहता है। इस प्रकार, यह उत्सव पूरे पांच दिन तक चलता है। '**जागत गांव हमार**' परिवार लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करता है कि सभी के घर धन-धान्य से भरे रहें। वैसे भी प्रदेश और केंद्र की सरकारों द्वारा किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। पशुपालन और बागवानी के लिए भी योजनाएं चल रही हैं। ये योजनाएं ग्रामीण-जनों के जीवन में उल्लास, प्रकाश, उमंग-उत्साह लाने और लक्ष्मीजी की कृपा प्रदान करने वाली हैं। खरीफकी उपज घर पहुंच चुकी है। किसान भाई रबी की फसल की बोवनी की तैयारी कर रहे हैं। जहां मसूर, चना और मटर की अगेती फसलें होती हैं, वहां इनकी बोवनी हो चुकी है। खाद-बीज की किल्लत दूर करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार युद्धस्तर पर प्रयास कर रही है और समस्या लगभग सुलझ चुकी है। किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बता चुके हैं कि प्रदेश में जल्द ही छह लाख टन डीएपी खाद आने वाली है। रबी की फसल जब आएगी, तो किसानों की खुशहाली बढ़ाएगी, किसान खुशहाल, तो सभी समाज खुशहाल, प्रदेश और देश खुशहाल...। वैसे भी लक्ष्मी मैया उन्हीं पर कृपा करती हैं, जो श्रम करते हैं, श्रमेण बसतलक्ष्मी, उद्यमेन बसतलक्ष्मी...। हम सब श्रम कर रहे हैं, तो लक्ष्मी का अह्वान ही कुल मिलाकर है। हम सब पर लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहे...। '**जागत गांव हमार**' परिवार की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली महापर्व की बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं...।

अजय द्विवेदी
संपादक

सीएम शिवराज ने बनाए मिट्टी के दीये, खजुराहो में कुम्हार के घर ही किया भोजन

वोकल फॉर लोकल मिट्टी के दीपक टैक्स फ्री

अरविंद मिश्र। भोपाल

मध्यप्रदेश में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कुम्हारों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। अब गांवों से शहरों में आकर मिट्टी के दीये बेचने वालों से नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूलेगी। हालांकि यह व्यवस्था अभी प्रदेश के चुनिंदा जिलों में ही लागू की गई। इसमें सबसे पहले भोपाल, होशंगाबाद के सिवनी-मालवा, सागर और दतिया जिला शामिल हैं। सरकार ने एक अभिनव पहल करते हुए नगरीय निकाय को निर्देशित किया है कि वे कुम्हारों से किसी तरह का कोई टैक्स ना लें और मिट्टी के सामान की बिक्री के लिए सभी को प्रोत्साहन दें। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में दीपावली पर वोकल फॉर लोकल का नारा दोहराया था। इधर, पीएम के आह्वान पर मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुट गए हैं कि राज्य में मिट्टी के दीयों का भरपूर इस्तेमाल हो। यही नहीं, सीएम शिवराज सिंह खजुराहो पहुंचे। वहां से वे राजनगर के धमना गांव गए और कुम्हार समाज के लोगों की समस्याओं को जाना। धमना गांव में नोनेलाल प्रजापति के घर गए। वहां उन्होंने खुद भी दीये बनाने की कोशिश की। इस दौरान वहां बने दीये और दीपावली के खिलौनों का अवलोकन भी किया। सीएम को बताया गया कि मिट्टी के बर्तन, खिलौने, दीये और टेराकोटा का सामान इलाहाबाद, भोपाल, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और गुजरात के अन्य शहरों में बेचा जाता है।

» भोपाल कलेक्टर के फैसले से जिले के कुम्हारों में खुशी

» दतिया में कुम्हारों के सामानों की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं

» सागर के कुम्हारों को उम्मीद, इससे घर में आएगी खुशहाली

» सिवनी-मालवा में नगर पालिका भी अब नहीं वसूलेगी टैक्स

भोपाल में दीपावली के दौरान मिट्टी के दीये बेचने वालों से नगर निगम कोई टैक्स नहीं वसूलेगा। वे बाजार में बिना किसी टैक्स के दुकान लगा सकेंगे। दीपावली पर कुम्हार समाज के लोग एवं अन्य ग्रामीण मिट्टी के दीये बनाकर बाजारों में बेचने लाते हैं। नगरीय क्षेत्र में भी इनसे किसी तरह के टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी।

अविनाश लवानिया, कलेक्टर, भोपाल

मिट्टी के दीपक को टैक्स फ्री किया है। नगरीय क्षेत्रों में मिट्टी के दीप बेचने वाले कुम्हारों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए भी आदेश दिए गए हैं। दीपावली जिले के ग्रामीणों द्वारा मिट्टी के दीपक बनाए जाते हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में इनसे किसी प्रकार की वूसली नहीं की जाए। लोगों को मिट्टी के दीये के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

दीपक आर्य, कलेक्टर, सागर

दीवाली पर मिट्टी के दीये बेचने वालों से नपा या ग्राम पंचायत कोई टैक्स नहीं वसूलेगी। व्यवसाय के दौरान उन्हें किसी प्रकार से परेशान हीं किया जाएगा। बाजार में चाइना के दीपक और दूसरे सामान आ जाने से मिट्टी के दीयों की मांग घट गई है। नपा व पंचायत द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स उन्हें परेशान करता था। अब वसूली नहीं होगी

संजय कुमार, कलेक्टर, दतिया

होशंगाबाद के सिवनी-मालवा में दीपावली पर्व के अवसर पर मिट्टी के दीये बेचने वालों से नगर पालिका कोई टैक्स नहीं वसूलेगी। बाजार में बिना टैक्स या किराये मिट्टी के दीये की दुकान लगा सकेंगे। वोकल फॉर लोकल के चलते यह आदेश जारी किया गया है। कुम्हार और अन्य ग्रामीण मिट्टी के दीये बनाकर बाजारों में बेचने लाते हैं।

अखिल राठौर, एसडीएम, सिवनी-मालवा

जब विस अध्यक्ष ने काटी धान की फसल

» गांव-गांव पहुंचकर किसानों से हुए रूबरू

» जनता से मिलने शुरू की थी सायकल यात्रा

भोपाल/रीवा। मैं पहले किसान हूं। फसलों की बोवनी और उसकी कटाई मैं भी जानता हूं। साथ ही मप्र के किसानों की परेशानी को भी अच्छी तरह से समझता हूं। हमारे किसानों की मेहनत का ही फल है कि हमें एक नहीं, बल्कि सात बार कृषि कर्मण अवॉर्ड मिला है। यह बात मप्र के विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपनी जनसंपर्क सायकल यात्रा के दौरान कही। दरअसल, देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पहाड़ी निरपत सिंह में जब गौतम की साइकल यात्रा पहुंची तो उन्होंने देखा की कुछ महिलाएं और पुरुष खेत में धान की फसल काट रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया और वो भी हसिया लेकर खेत में घुस गए और धान काटने लगे। तब वहां मौजूद सभी ग्रामीण दंग रह गए। तभी विस अध्यक्ष ने उक्त बातों को दोहराया। यही नहीं, वो धान काटने के बाद जनता-जनार्दन की बीच ढोलक वादन भी किया। विस अध्यक्ष अपनी सायकल यात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर किसानों के साथ आम जनता से रूबरू हुए। रविवार को सायकल यात्रा का सीएम शिवराज सिंह ने समापन किया।

मंदसौर के पांच अधिकारी निलंबित

सहकारी समितियों में उपार्जन घोटाला

भोपाल। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के दौरान बड़ा घोटाला हुआ है। सहकारी समितियों ने खरीदी पर तय सीमा से ज्यादा खर्च कर दिखाकर सरकार से राशि ले ली। मंदसौर जिले की 17 सोसायटियों ने 62 लाख का घोटाला किया। जांच के बाद सहकारिता आयुक्त ने पांच अफसरों का निलंबन कर प्रदेश के सभी जिलों से खर्च का ब्यौरा मांगा है। 2020-21 में मार्केटिंग एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं ने गेहूं व चने की खरीदी की। सरकार ने प्रति क्विंटल खरीदी व्यय 16.74 रुपए एवं गोदाम तक माल पहुंचाने के लिए 8 रुपए तय किए थे। जिन पर गाज गिरी है इनमें सहकारी निरीक्षक शंकरलाल बामनिया, सहकारी निरीक्षक आरके जैन, सहकारी निरीक्षक अनिल कुमार जैन, नानूराम सोलंकी अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी निरीक्षक विपिन बड़गोती शामिल हैं।

» गेहूं-चना खरीदी पर खर्च ज्यादा दर्शाया

» अब प्रदेश के सभी जिलों से मांगा ब्यौरा

पायलट प्रोजेक्ट की केंद्र सरकार ने दी सहमति: अब पता चल जाएगा कौन-कितनी ले रहा खाद

कृषि और सह-कारिता विभाग ने शुरू की तैयारी

प्रदेश में खसरे से रुकेगी खाद की कालाबाजारी

भोपाल। संवाददाता

केंद्र सरकार किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान देती है। इसका सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए अब मध्य प्रदेश में नया कदम उठाया जा रहा है। इसके तहत किसान कितनी खाद ले रहा है यह खसरे से लिंक किया जाएगा। इससे यह पता चलेगा कि जितनी खाद वो ले रहा है, उसके उपयोग के लिए भूमि है भी या नहीं। केंद्र की सहमति से एक जिले में यह पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा। दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा कराई गई जांच में यह बात सामने आई है कि यूरिया बड़ी मात्रा में ऐसे किसानों द्वारा लिया जा रहा है, जिसकी उन्हें दरकार भी नहीं है।

पिछले साल ऐसे 15 मामलों में एफआईआर कराई गई थी। इस बार प्रत्येक जिले में बड़े खरीदारों का सत्यापन कराया जा रहा है। प्रदेश में प्रतिवर्ष करीब 20 लाख टन यूरिया की दरकार होती है। केंद्र मांग के अनुरूप राज्य का कोटा तय करता है और खरीफ और रबी सीजन के अनुसार इसका आवंटन होता है। इसका वितरण सहकारी समितियों और निजी विक्रय केंद्रों के माध्यम से किया जाता है।

प्रबंधक-गोदाम प्रभारी पर एफआईआर

पिछले साल प्रत्येक जिले में बड़े यूरिया के खरीदार किसानों की जांच कराई थी। इसमें होशंगाबाद, सतना सहित अन्य जिलों में गड़बड़ी उजागर हुई थी। होशंगाबाद की गढ़ाघाट सहकारी समिति में 90 क्विंटल यूरिया संदीप प्रजापति के नाम बेचना बताया था, जबकि वह किसान नहीं हम्माल था। बाद में समिति के सहायक प्रबंधक नारायण पटेल और गोदाम प्रभारी संजीत बर्मन के खिलाफ एफआईआर कराई गई।

सतना में फर्जीवाड़ा

इसी तरह सतना में फूलचंद गुप्ता ने आठ किसानों को अत्याधिक मात्रा में यूरिया बेच दिया। जबकि, बिना पाइंट आफ सेल्स मशीन के खाद नहीं बेची जा सकती है। इसमें समिति के सदस्य किसानों का पूरा ब्योरा रहता है पर समिति के कर्मचारी किसी एक व्यक्ति के नाम पर खाद बेच रहे थे। इस गड़बड़ी को अब पूरी तरह से रोकने के लिए खाद वितरण को खसरे से लिंक करने का प्रोजेक्ट किया जाएगा और परिणाम का आकलन करके इसे पूरे प्रदेश में लागू करने संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

इन पर हो चुकी एफआईआर

इंद्रलाल गुप्ता, भगवानदीन गुप्ता और तेजभान कुशवाह रीवा, मेसर्स सोनी ट्रेडर्स सिहावल, जयपाल सिंह भदौरा, अनिल ट्रेडर्स मडवास, शिवेन कुमार मिश्रा पथरोला, शंभुलाल राठौर सविधा फर्टिलाइजर बड़वानी, शकील अहमद खान पिछोर, महशे शर्मा गोदाम प्रभारी दतिया, राजेश शुक्ला गोदाम प्रभारी इंदरगढ़, रमेश कटारे सहकारी संस्था भिंड, नारायण पटेल और संजीत वर्मन पिपरिया, रामसिया गुप्ता सहकारी विपणन संघ खेडा इटारसी।

चुनिंदा लोग ले गए यूरिया

प्रदेश सरकार खाद के उन खरीदारों की जांच करा रहे हैं, जो हजारों बोरी यूरिया ले जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे किसानों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। इनमें खरगोन के सुरेश (4,781 बोरी), शिवानी (1,976 बोरी) राहुल वर्मा (1,750 बोरी), उज्जैन के दिनेश विक्रम (2,557 बोरी) और राजेश माली (2,080 बोरी), बैतूल के नर्मदा प्रसाद (2,401 बोरी), होशंगाबाद के सुकर्ण विश्वकर्मा (1,850 बोरी), जितेंद्र लोवंशी (1,800), विनोद कुमार गौर (1,800 बोरी) और छिंदवाड़ा के आर काकोदिया (1,905 बोरी) शामिल हैं।

प्रदेश और केंद्र सरकार का मकसद खाद की वितण व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। खसरे में किसान का आधार नंबर रहता है। इसे खाद विक्रय से जोड़ेंगे ताकि उसकी भूमि और फसल संबंधी सारी जानकारी मिल जाए। इसका फायदा खाद संबंधी कार्ययोजना बनाने में मिलेगा।
अजीत केसरी, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग

मंदसौर, नीमच, सुवासरा के बाद उज्जैन जिले में भी बढ़ा रुझान

अश्वगंधा की खेती से उज्जैन में किसान कमा रहे पांच गुना मुनाफा

उज्जैन। संवाददाता

तहसील के किसान औषधीय खेती कर सामान्य से पांच गुना अधिक लाभ कमा रहे हैं। तहसील के रूपाहेड़ा गांव के प्रगतिशील किसान भौमसिंह पंवार ने एक बीघा रकबा में अश्वगंधा की बोवनी की थी। लागत खर्च निकाल कर सवा लाख रुपए की कमाई हुई। आयुर्वेद औषधि निर्माता ब्रांडेड कंपनियां आयुर्वेद उत्पादों को किसानों से अच्छे दाम में खरीदती हैं। कृषक भौमसिंह ने पिछले साल एक बीघा में अश्वगंधा का 6 किलो बीज बोया था, जिसमें अश्वगंधा की उपज चार क्विंटल हुई और नीमच मंडी में उसकी जड़ 35 हजार रुपए प्रति क्विंटल बेची। पत्तियों का भूसा 12 हजार में बेचा। इस प्रकार आय एक लाख 52 हजार लागत खर्च 25 हजार रुपए काट के शुद्ध लाभ मिला एक लाख 27 हजार हुआ। इस बार भौमसिंह ने पांच बीघा में अश्वगंधा उगाया है। एक बीघा में लागत बीज की कीमत 2 हजार रुपए, डीएपी उर्वरक एक थैली कीमत 1200 रुपये, निंदाई-कटाई एवं उखाड़ने की मजदूरी 20 हजार सहित कुल लागत खर्च आया 25 हजार आएगा।

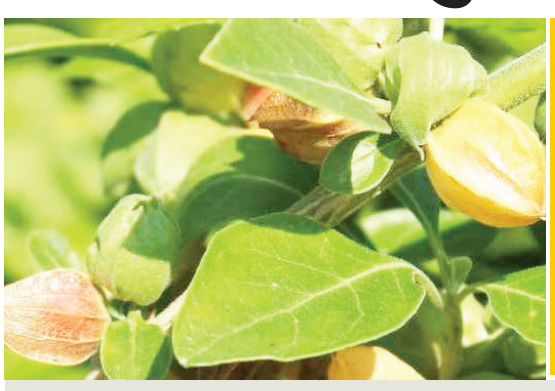

पशु भी नहीं खाते

किसान पंवार ने बताया कि एक बीघा में सोयाबीन बोने पर चार क्विंटल के औसत से 30 हजार रुपए की ही कमाई होती, जबकि अश्वगंधा से एक बीघा में सवा लाख रुपए की कमाई हुई। अश्वगंधा की खड़ी फसल को मवेशी भी नहीं खाते। बकरे, घोड़ा आदि जानवरों को इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है, जिससे इसकी सुरक्षा करने बागड़ लगाने की भी जरूरत नहीं है।

अश्वगंधा औषधीय खेती है। तीन से साढ़े तीन माह में फसल तैयार हो जाती है। अश्वगंधा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है। हर तरह की बीमारी में बिना साइड इफेक्ट के काम करती है। अश्वगंधा को बोने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए शासन को चाहिए कि इसे उद्यानिकी विभाग की योजना में शामिल करना चाहिए।
डॉ. राजेश्वरी मेहरा, आयुष चिकित्सक

रबी सीजन में कृषक भौमसिंह पंवार एवं कृषक शैलेंद्रसिंह राठौर सहित जिले के किसानों ने इस सीजन में करीब 25 हेक्टेयर में अश्वगंधा की फसल उगाने के लिए 15 अक्टूबर को इसकी बोवनी कर दी है। इस फसल की जड़ें एवं पत्तियां दोनों बिकती हैं। आयुर्वेदिक खेती दोनों खरीफ एवं रबी सीजनों में बोने की सलाह किसानों को दी है। खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए। रबी सीजन में 4 बार सिंचाई पर्याप्त है।
ज्योति शर्मा, ग्रामीण विकास अधिकारी, उद्यानिकी विभाग नर्सरी ग्राम मौलाना

अन्य प्रांतों की अपेक्षा अश्वगंधा की फसल देश के पंजाब, राजस्थान के अलावा अब मप्र के मंदसौर, नीमच, सुवासरा एवं अब उज्जैन जिले में भी इसको बोने की शुरुआत हुई है। बरसात के सीजन में जून माह में और रबी सीजन में 15 अक्टूबर तक अश्वगंधा की बोवनी करनी चाहिए। कम नमी होने पर बारिश के मौसम में ढलान वाले खेतों में यह फसल अधिक मुनाफा देती है।
अनिल कुमार सक्सेना, कृषि विस्तार अधिकारी

सरकार दे रही आलू के प्रमाणित बीज पर सब्सिडी

भोपाल। संवाददाता

मप्र सरकार राज्य में आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रमाणित बीज एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवा रही है। चयनित जिलों के किसानों से आलू के प्रमाणित बीज के साथ कीटनाशक दवा, स्प्रे मशीन अनुदान पर देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

मध्यप्रदेश में अभी सब्जी प्रदर्शन कार्यक्रम (आलू) योजना के तहत 4 जिलों शिवपुरी, उज्जैन, सागर, शाजापुर जिलों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। इन चार जिलों के लिए 600 इकाई का लक्ष्य रखा गया है। योजना केवल अनुसूचित जाति के कृषक के लिए है। जिलों के अनुसार लक्ष्य इस प्रकार है, शिवपुरी-200, उज्जैन-200, सागर-183 संख्या, शाजापुर-17।

किसानों को सामग्री दी जाएगी: चयनित किसानों को भौतिक लक्ष्य के अनुसार आलू बीज के साथ अन्य सामग्री भी दी जाएगी। एक किसान को 0.1 हेक्टेयर के लिए 200 किलोग्राम प्रमाणित आलू बीज 25 रुपए किलो की दर से 5000 रुपए तक का आलू बीज दिया जाएगा। इसके साथ बैटरी कम हैंड स्प्रेयर पम्प 1 दिया जाएगा जिसकी कीमत 3,175 रुपए है। प्लास्टिक केट 4 दिए जाएंगे जिसका मूल्य प्रति केट 450 रुपए है, जिसका कुल 1800 रुपए लिए जाएंगे।

किसानों को आलू प्रदर्शनी कार्यक्रम के तहत प्रमाणित बीज के साथ-साथ खेती के लिए आवश्यक अन्य सामग्री भी दी जाएगी। यह सभी सामग्री किसानों के लिए अनिवार्य है। किसानों को प्रमाणित आलू बीज के साथ, बैटरी कम हैण्ड स्प्रेयर पम्प, प्लास्टिक केट इत्यादि सामग्री भी दी जाएगी।

कैसे मिलेगी सब्सिडी

आलू प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए प्रति इकाई निर्धारित लागत राशि 10,000 रुपए है। आलू बीज एवं आवश्यक सामग्री की वास्तविकता कीमत निर्धारित इकाई लागत से कम होने पर शेष/अंतर की राशि से कृषक द्वारा अन्य आवश्यक सामग्री स्वयं क्रय की जाकर जिले के उप/सहायक संचालक उद्धान को देयक प्रस्तुत किया जाएगा, देयक के सत्यापन उपरांत राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषक को किया जाएगा।

मध्यप्रदेश में मिलीं 150 प्रजाति की तितलियां

भोपाल -उज्जैन बन गया तितलियों का गढ़

प्रदेश में तितलियों का संसार

» भोपाल में रातापानी के जंगल में दुर्लभ तितलियां मिलीं

» 14 राज्य के 88 विशेषज्ञ तीन दिन तक घूमे अभयारण्य

» तितलियों की 103 प्रजातियां मिली, इनमें कई दुर्लभ भी

» सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 126 प्रजाति की तितलियों की पहचान

भोपाल/उज्जैन। वंदना बृजेश परमार

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 50 किमी दूर स्थित 823 वर्ग किमी में फैले रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में 103 से अधिक प्रजातियों की तितलियां पाई गई हैं। यह आंकड़ा सितंबर 2021 में 13 राज्यों के 88 तितली विशेषज्ञों के द्वारा दो दिन जंगल की खाक छानने के बाद जारी किया गया। वहीं उज्जैन वन मंडल के नौलखी के ईको टूरिज्म पार्क में प्रथम तितली सर्वेक्षण का कार्य किया गया। इस दौरान 28 प्रकार की तितलियां और 36 प्रकार के पक्षी पाए गए। हालांकि देश के अलग-अलग राज्यों में तितलियों की 14,00 प्रजातियां होने का अनुमान है। इनमें से मप्र में करीब 150 प्रजातियां की पहचान की जा चुकी। वन विहार नेशनल पार्क में 2015 व 2020 में हुए सर्वे में 36 प्रजातियां मिली हैं। इनमें ब्लू टाइगर, फैंसी, मोरमोन, कामन ग्रास यलो, प्लेन टाइगर आदि शामिल हैं। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और हिल स्टेशन पचमढ़ी में 2017 में किए सर्वे में 126 प्रजातियां मिली थीं। इनमें इंडियन नवाब, कामन नवाब, आरेंज आकलीफ, काल जेजेबेल आदि शामिल हैं। अब उत्साही वन विशेषज्ञ तितलियों के संरक्षण की कवायद में जुट गए हैं।

बर्ड सर्वे की गुजारिश

सर्वे में मप्र के अलावा छढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, प. बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, यूपी समेत 13 राज्य के एक्सपर्ट शामिल हुए। इन्हें आने वाले बर्ड सर्वे में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। तितलियों पर हुए सर्वे में वाइल्ड वारियर्स और तिंसा फाउंडेशन का सहयोग भी रहा।

तितलियों से फायदा

अब रातापानी में तितलियों को संरक्षित करने की योजना बनेगी। जंगल का संरक्षण और बढ़ेगा। खाद्य श्रृंखला मजबूत होगी। बाघ, तेंदुए समेत दूसरे वन्यजीवों को फायदा होगा। जंगल का संरक्षण बढ़ने से वन्यजीवों की आबादी भी बढ़ेगी। रातापानी पहुंचने वालो पर्यटकों को बाघ, तेंदुए समेत दूसरे वन्यप्राणी व तितलियां आसानी से नजर आएंगी।

13 राज्यों की टीम

राजधानी भोपाल के रातापानी वन्यजीव अभयारण्य में 103 से अधिक प्रजातियों की तितलियां पाई गई हैं। यह आंकड़ा सितंबर 2021 में 13 राज्यों के 88 तितली विशेषज्ञों के द्वारा दो दिन जंगल की खाक छानने के बाद जारी किया गया। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद भोपाल से सटे इस जंगल की गुणवत्ता को लेकर चर्चा हो रही है।

भोपाल वन विहार में सिर्फ तीन दर्जन

भोपाल शहर स्थित वन विहार नेशनल पार्क के तितली उद्यान में पिछले वर्ष करीब तीन दर्जन तितलियां देखी गई हैं। वर्ष 2014 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (आईआईएफएम) के कैंपस में हुए अध्ययन में तितलियों की 55 प्रजातियां देखी गई थी। जानकार मानते हैं कि शहरों के आस-पास प्रदूषण और खेती-बाड़ी के बदलते तरीकों की वजह से तितलियों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में भोपाल से सटे जंगल से आया यह आंकड़ा जंगल की गुणवत्ता को लेकर क्या एक अच्छा संकेत है। रातापानी के जंगल में तितलियों की प्रजाति और संख्या देखने के अलावा शोधकर्ताओं को एक और बात उत्साहित कर रही है, वह है दुर्लभ प्रजातियों की तितलियों का मिलना। इस सर्वे में लगभग 6 -7 दुर्लभ प्रजातियों की तितलियां दिखी हैं जिसमें से कुछ ऐसी हैं जो वर्षों बाद नजर आई हैं। चमढ़ी बुश ब्राउन, जो कि मध्यप्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी की तितली है। रातापानी के जंगल में देखी जा रही हैं। रातापानी में इस तितली के दिखने का मतलब है कि अभयारण्य इस तितली के लिए

अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर रहा है। ब्लैक राजा , एंगल्ड पियरो, नवाब, कॉमन ट्रीब्राउन, ट्राई कलर्ड पाइड फ्लेट जैसी कई और दुर्लभ प्रजातियों की तितलियां भी यहा विशेषज्ञों को नजर आईं।

खेती का बदला तरीका चिंतनीय

जानकार जंगल के आसपास हो रहे रासायनिक खेती को लेकर चिंतित हैं। 103 प्रजातियों की तितलियां जिस स्थान पर देखी गई हैं उसके आसपास खेतों में रसायनों का प्रयोग होता है। इसका तितलियों पर बुरा असर हो सकता है। इस अभयारण्य के आस-पास और भीतर इंसानी आबादी मौजूद है। गांव के लोग खेती करते हैं और कीटनाशकों का उपयोग भी करते हैं जिस से तितलियों के अंडे मर जाते है। साथ ही,कैटरपिलर जहरीली पत्तियों को खा कर मर जाते हैं, जिन से तितलियों की संख्या प्रभावित हो सकती है।

पशुओं से फायदा

हालांकि गांव में लोगों की वजह से फायदा भी हो रहा है। लोग पशु-पालन करते हैं उस से जंगल में ताड़ी खाद उपलब्ध होती है, और यहा पेड़ और अच्छे से उग पाते हैं। यहां जानवर, इंसान और पौधों के बीच एक संतुलन बना हुआ है जिस से होस्ट और नेक्टर प्लांट्स उग रहे हैं और तितलियों को भरपूर मात्रा में पोषण और रहने की जगह मिल रही है। इस अभयारण्य में अमलतास, अशोक, लंटाना, कैथ, सड़ेद शिरीष, आक, नींबू, करीपत्ता, मदार जैसे होस्ट प्लांट्स पाए जाते हैं जिन के कारण यहा कई प्रजातियों की तितलियां मिलीं।

उज्जैन के ईको टूरिज्म पार्क में 28 प्रकार की तितलियां

इधर, उज्जैन के ईको टुरिज्म पार्क में किए गए प्रथम सर्वेक्षण में 28 प्रकार की तितलियां और 36 प्रकार के पक्षी पाए गए हैं। यह सर्वेक्षण वन्य प्राणी विशेषज्ञों एवं वन विभाग के दल ने संयुक्त रूप से पार्क के सम्पूर्ण क्षेत्र का भ्रमण/निरीक्षण करने पर सामने आया है। रेंजर कौसंबी झा के अनुसार ईको टूरिज्म पार्क में प्रथम तितली सर्वेक्षण का कार्य 24 अक्टूबर को किया गया। इस प्रथम सर्वेक्षण में विशेषज्ञ के रूप में सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी शामिल थे। एक दिवसीय सर्वेक्षण में सुबह के दो घंटे के समय में अलग अलग ग्रुप ने पार्क में अलग-अलग स्थान पर तितलियों और पक्षी को देखकर इंगित किया। मुख्य वन संरक्षक वृत्त उज्जैन, और समस्त वन स्टाफकी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। वन्यप्राणी विशेषज्ञों तथा वन विभाग के दल द्वारा संयुक्त रूप से मनोरंजन पार्क के संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण/निरीक्षण किया गया। इस दौरान 28 प्रकार की तितलियां और 36 प्रकार के पक्षी पाए गए, जिनके संरक्षण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर निर्देश दिए गए।

उज्जैन में चार-चांद लगा रहा नौलखी वनक्षेत्र

उज्जैन में विशेष रूप से स्पाटेट पाईरोट, थ्री स्पाट ग्रास यलो,स्ट्रीप्ड टाईगर किस्म की तितलीयां देखी गईं। इसी प्रकार पक्षियों मे व्हाईट आई बर्जड,शार्ट टोड स्नेक ईगल, ट्री पीप्ट,बे बेक्ड शीक देखे गए। उपस्थित विशेषज्ञों को सम्मान स्वरूप प्रमाण-पत्र वितरित कर उक्त कार्य में रुचिपूर्ण सहयोग व प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उज्जैन वन मंडल के अन्तर्गत उज्जैन के आरक्षित वन खंड नौलखी कक्ष क्र. 24 में वन एवं वन्यप्राणी के अनुभव/संरक्षण एवं पर्यटकों के मनोरंजन के लिए ईको टूरिज्म पार्क सन 2018 से प्रारंभ किया गया है। उज्जैन के चारों ओर लगभग 118 किलो मीटर का पंचक्रोशी परिक्रमा मार्ग नौलखी वनक्षेत्र के अंदर से गुजरता है।

कमल तालाब बना आकर्षण का केंद्र

ईको टूरिज्म पार्क में इंटरप्रीटेशन सेंटर, नौकायन, पक्षी दर्शन, कैंपिंग, ट्रेकिंग और सायकलिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उक्त क्षेत्र में राशि वन, नक्षत्र वन, शोभादार एवं अन्य पौधों का रोपण कार्य किया गया है। इसका रख-रखाव संबंधी कार्य वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि नौलखी ईको टूरिज्म पार्क शहर की चकाचौंध के बीच में स्थित होकर वन और वन्यजीव के प्रेमियों, बच्चों, फोटोग्राफर और पर्यटकों के लिए एक बहुत ही अच्छा केंद्र है। यहां पर पार्क की सुंदरता तथा पर्यटकों के आकर्षण के लिए कमल तालाब भी बनाया गया है। इंटरप्रीटेशन सेंटर में वन/वन्यप्राणियों से संबंधित त जानकारी संग्रहित है।

जलवायु के अनुकूल पशुपालन की जरूरत

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी

खेती-बाड़ी के साथ पशुपालन सहायक व्यवसाय के रूप में पुरातन प्राचीन काल से ही ग्रामीणों और किसानों की आजीविका का अति महत्वपूर्ण अंग रहा है। लोगों द्वारा पशुओं का लालन-पालन खेती-बाड़ी से पहले ही अंगीकार कर लिया गया था। फिर धीरे-धीरे पशुओं के सहयोग से खेती-बाड़ी करना शुरू हुआ। इसलिए यह कहा जाता है कि पशुपालन भारतीय कृषि की रीढ़ रहा है। मशीनीकरण के दौर में खेती-बाड़ी में पशुओं का प्रयोग भले ही नगण्य हो गया है, लेकिन पशुपालन का महत्व कम नहीं हो जाता है। पुरातन काल में भारत में पाले जाने वाले पशुओं पर नजर डाली जाए तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहां गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मिथुन, याक, घोड़ा, ऊंट आदि की नस्लों को एक क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुकूल ही प्रमुखता दी जाती थी।

बदलते जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पशुपालन के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां उभरकर सामने आ रहीं हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम आसानी से देखे जा सकते हैं। जिनका प्रभाव खेती-बाड़ी के साथ पशुपालन पर पड़ने लगा है। दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन प्रभावित होने से लेकर उनके विकास, प्रजनन और पशु रोगों पर असर आसानी से देखा जा सकता है। आने वाले समय में यदि यही रुख जारी रहा तो जलवायु परिवर्तन के खतरे पशुपालन के समझ गंभीर चुनौतीयां बनकर उभरेंगे। आज देश के कई भागों में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की अलग-अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, कम होती सर्दी, घटते बरसात के दिन, बढ़ता तापमान यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। तापमान में बढ़ोत्तरी से सर्दियों के दिन कम होने के साथ ही गर्मियों के दिनों में बढ़ोत्तरी हो रही है जिससे उत्तर भारत में दुधारू पशुओं से प्राप्त होने वाले दुग्ध उत्पादन और उनके प्रजनन में गिरावट देखी जा सकती है। इसका प्रभाव पशुपालन पर आसानी से देखा जा सकता है। यदि अभी से इस दिशा में प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में इसके घातक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का ही असर है कि पशुधन की संख्या में कमी आ रही है। उत्तर भारत में पशुपालकों द्वारा गायों की बजाए भैंस पालन ज्यादा जोर दिया जाता है। भैंस एक सीजनल ब्रीडर है जो कि बरसात से लेकर सर्दियों तक ही गर्मी में आकर गर्भधारण करती है। पशुओं का वृद्धि एवं विकास उनके जीनोटाइप एवं पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तापमान के बढ़ने पर पशुओं की शारीरिक प्रतिक्रियाओं में वृद्धि होती है जिससे कार्डियोपल्मोनरी और उसकी तीव्रता की क्षमता प्रभावित होती है। थर्मल स्ट्रेस के कारण डेयरी पशुओं के दुग्ध उत्पादन में गिरावट, समय से गर्मी में न आने तथा गर्मी के लक्षण प्रकट नहीं करने तथा गर्भ धारण नहीं होना प्रमुखता से देखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते इसी प्रकार से आगे भी तापमान में वृद्धि जारी रही पशुओं में साइलेंट हीट, छोटा मदकाल और प्रजनन क्षमता में ओर अधिक गिरावट आयेगी। जलवायु परिवर्तन के कारण पशु रोगों में भी ओर अधिक वृद्धि होगी। इन पर काबू पाने के लिए अभी से हर संभावित प्रयास करने की जरूरत है। पशुओं के आवास में पर्यावरण के अनुकूल संशोधन करके सूर्य के सीधे आने प्रकाश को रोका जा सकता है। पानी का छिड़काव और पंखे आदि लगाकार तापमान और गर्मी को कम किया जा सकता है। पशुओं का आवास ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां पेड़ों की घनी छांव हो अथवा पशुशाला के आसपास चारों और पेड़-पौधे लगाकर भी तापमान एवं सीधे आने वाली सूर्य किरणों और धूप को काफी हद तक रोका जा सकता है। पशु आवास को उचित

तरीके से डिजाइन करना चाहिए जिससे हवा का आवागमन बढ़ने के साथ ही प्राकृतिक रूप से प्रकाश और हवा अंदर आती रहे। पशु आवास में पानी की बौछार का प्रयोग करके पशुओं को प्रभावित करने वाले थर्मल हीट स्ट्रैस को कम किया जा सकता है। पशुओं को पौषणयुक्त आहार खिलाने की रणनीति अपनानी चाहिए जिससे हीट स्ट्रैस के कारण पशुओं के उत्पादन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। पशुओं के आहार में सभी प्रकार के ऐसे घटक मिलाने चाहिए जिससे उसका आहार संतुलित हो सके। पशुओं के आहार में पोटेशियम, सोडियम, मैगनीशियम, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम आदि खनिज लवणों को उपयुक्त मात्रा में शामिल करने से गर्मी के प्रभाव को कम करने के साथ ही पशुओं से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। पशु आहार में पोषण की दृष्टि से फीड एडीट्व्स ऊष्मागत तनाव को कम करने में लाभदायक होते हैं। सामान्यतौर पर फीड एडीट्व्स गर्मी की अधिकता को कम करने के साथ ही पशुओं के शरीर के अंदरूनी तापमान को कम करते हैं। पशुओं को गर्मियों के दिनों में ठंडे समय पर अर्थात सुबह और देर शाम में चारा-दाना खाने को देना उपयुक्त रहता है। पशुओं को एक साथ खिलाने की बजाए थोड़ा-थोड़ा करके दिन में कई बार खाने को देना चाहिए। आहार देने के बाद यदि पानी की उपलब्धता नहीं है तो उत्पादन प्रभावित होता है। अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए भी लगातार पानी पिलाते रहना आवश्यक है। इससे पशुओं के शरीर का तापमान कम करने में मदद मिलती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लंबे समय तक कम करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पशुओं की ऐसी नस्लें विकसित की जाएं जो कि आनुवांशिक रूप से अधिक उत्पादन, प्रजनन एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से सक्षम होने के साथ ही बदलती जलवायु के प्रति सहनशील हों। वर्तमान में पशुओं की आनुवांशिक संरचना में बदलाव करके जलवायु सहनशीलता के अनुकूल नस्लें विकसित करने की जरूरत है। जिनमें अत्यधिक गर्मी, सर्दी आदि को सहने एवं अधिक उत्पादन, वृद्धि, रोगों से लड़ने की क्षमता हो। पशु रोगों पर प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिये सतर्कता और निगरानी तंत्र को बहुत अधिक मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। आज जिस तरीके से देश में अधिक दुग्ध उत्पादन लेने के लिए विदेशी क्रॉसब्रीड गाय की नस्लों को बढ़ावा दिया गया। उससे भारतीय नस्लों के संरक्षण एंव संवर्धन में रुकावट पैदा हुई है। फलस्वरूप आज क्रॉसब्रीड गाय कई क्षेत्रों में अनेकों समस्याओं जैसे-बांझपन, बार-बार गर्मी में आना परंतु गर्भ नहीं ठहरना, थनैला आदि गभीर समस्याओं के चलते लाभ की बजाए घाटे का कारण ही बन रही हैं। इन गायों का दूध भी आज एक अहम चर्चा का विषय बनकर सामने आ रहा है। वैज्ञानिकों से लेकर आम जागरूक लोगों में ए-1 एवं ए-2 दूध के प्रति जिज्ञासाओं से लेकर गंभीर चिंताएं देखी जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लिखी नई इबारत

मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक नई इबारत लिखी जा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सड़क, रोजगार के साथ स्वच्छता के क्षेत्र में भी विशेष प्रयास लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्र सरकार की योजनाओं सहित राज्य सरकार की विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर ग्राम विकास की अवधारणा को साकार किया है।

कारोना काल में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने में महात्मा गांधी नरेगा योजना ने बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड काल में 18 लाख से अधिक नवीन जॉबकार्ड जारी किए गए। कोविड काल में 34 करोड़ से अधिक मानव दिवसों का सृजन हुआ, जो योजना के प्रारंभ से अभी तक का सर्वाधिक है। इस वित्तीय वर्ष में माह सितम्बर तक 76 लाख से अधिक ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर 19 करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन हुआ है। इस अवधि में करीब सवा 2 लाख सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्य पूर्ण किए गए और 12 लाख 80 हजार से अधिक कार्य अभी प्रगतिरत हैं। मध्यप्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में लगभग 20 लाख अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को साढ़े 8 करोड़ से अधिक मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों को मनरेगा से रोजगार उपलब्ध कराने में मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन: इस मिशन में प्रदेश के 52 जिलों के 45 हजार 135 ग्रामों में सघन रूप से कार्य किया जा रहा है। अब तक 3 लाख 36 हजार से ज्यादा समूहों का गठन कर लगभग 38 लाख 31 हजार परिवारों को जोड़ा जा चुका है। साथ ही 282 करोड़ रूपये परिक्रामी निधि (रिवाल्विंग फण्ड), 765 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश निधि तथा बैंक ऋण के रूप में 2121 करोड़ रूपये का वितरण किया गया है। कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों से 13 लाख 37 हजार परिवारों को तथा गैर कृषि आधारित गतिविधियों से 5 लाख पांच हजार परिवार जुड़े हुए हैं। मिशन के माध्यम से 53 हजार ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा 2 लाख 86 हजार युवाओं को स्व-रोजगार प्रशिक्षण दिलाया गया है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार मेलों से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में भी 2 लाख 4 हजार से ज्यादा ग्रामीणों को स्व-रोजगार शुरू करने के लिए ब्याज रहित ऋण वितरण किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में एक लाख 12 हजार 613 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय और 1,990 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निमाज़्ण किया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 1,930 ग्रामों में घर-घर कचरा संग्रहण कार्य और 15 हजार 445 सामुदायिक कम्पोस्टिंग के कार्य पूर्ण किए गए। तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतगज़्त 20 हजार 684 सामुदायिक सोक पिट तथा 83 हजार 512 घरेलू सोक पिट के निर्माण पूर्ण किए गए। गोवर्धन परियोजना में 7 बायो गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। द्वितीय चरण में 172 गौशालाओं में बायो गैस संयंत्र स्थापना का प्रस्ताव है। इस वर्ष अभी तक 591 ग्रामों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। वर्तमान में मिशन के विभिन्न घटक की प्रगति में मप्र स्वच्छता में उत्कृष्ट राज्यों में शामिल है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण: योजना में मध्यप्रदेश देश में आवास निर्माण में प्रतिशत के आधार पर बड़े राज्यों में द्वितीय एवं संख्या के आधार पर तृतीय स्थान पर है। अब तक 21 लाख 9 लाख आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 4 लाख 45 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य है।

मध्याह्न भोजन: प्रदेश की 1 लाख 13 हजार शालाओं के 66 लाख 25 हजार छात्रों को 71 हजार महिला स्व-सहायता समूहों तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही भोजन पकाने की राशि के समतुल्य राशि तथा खाद्यान्न भी प्रदाय किया जा रहा है। इस कार्य में लगे रसोइयों को प्रतिमाह प्रति रसोइया 2 हजार रुपए मानदेय उनके खातों में दिया जाता है। लक्षित शालाओं में से 94 हजार शालाओं में किचिन शेड का निर्माण किया जा चुका है। एक लाख 6 हजार शासकीय शालाओं में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जो एक नवाचार है। विगत दो वर्षों में 12 हजार 57 मां की बगिया का निर्माण पूर्ण हुआ है और 5229 बगिया प्रगति पर हैं। प्रदेश के 75 अति कुपोषित विकासखंड में प्राथमिक शाला के छात्रों के पोषण स्तर में सुधार के लिए गुड़ एवं मूंगफली से बनी हुई चिक्की के वितरण की सराहना केन्द्र सरकार ने भी की है।

राम वन गमन पथ

राम गोपाल सोनी

मेरी इस पुस्तक से जहां एक ओर राम वन गमन के वास्तविक पथ का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं ऐसे महत्वपूर्ण संतों के आश्रमों और उनके महत्व को लोग जान सकेंगे। कालांतर में इन क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मैंने राम के प्रथम वन गमन जब वो ऋषि विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ रक्षा में गए थे के मार्ग का भी वर्णन किया है। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण कर जनकपुरी गए और मार्ग में हजारों वर्षों से श्रापित पत्थर की मूर्ति बनी अहल्या का उद्धार किया था और जनक के बुलाने पर धनुष यज्ञ में शामिल होकर धनुष भंग किया। जिससे जनक पुत्री सीता के साथ उनका ब्याह हुआ और बाद में शेष तीनों भाइयों का ब्याह जनक और उनके भाई की पुत्रियों से हुआ था। मैंने राम वन गमन पथ को, राम चरित मानस और बाल्मीक रामायण के आधार पर तथा भौगोलिक तथ्यों के आधार पर प्रामाणिक जानकारी जुटाकर इस पुस्तक में संकलित किया है। मेरे द्वारा राम वन गमन पथ के ग्रामों की गूगल नक्शे से हवाई दूरी और उन स्थानों के अक्षांस

और देशांतर दिए हैं जिससे पथिक आसानी से पदयात्रा या वाहन से यात्रा कर राम के पथ में चलकर भव बंधन से अपने को छुड़ा सकेंगे। भगवान श्रीराम की कृपा से इस लोक और परलोक में क्रमश: ऐश्वर्य और परम गति पा सकेंगे। भगवान श्री राम के पथ के अंश भाग में भी पूरे भक्ति, भाव से पद यात्रा करने से उन सभी राम भक्तों को प्रभु श्री राम की अवश्य कृपा होगी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने राम चरित मानस में लेख किया है कि अगर आज भी राम-सीता और लक्ष्मण को स्वप्न में भी बटोही रूप में हृदय में धारण कर लें, तो उन्हें राम का वो पथ मिल जाएगा, जिसको मुनि लोग जोग-जप करके प्राप्त करते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि भगवान श्रीराम की कृपा से यह पुस्तक लोगों को राम वन गमन पथ में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी और भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , तेलंगाना , आंध्र प्रदेश , कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संपूर्ण विश्व में सनातन हिन्दू धर्म के उच्च आदर्शों की स्थापना होगी। संपूर्ण भारत तथा विश्व में राम नाम की महिमा,राम के आदर्श और राम राज्य की स्थापना की दिशा में एक मजबूत आधार बनेगी और विश्व बंधुत्व तथा वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श को स्थापित करेगी।

ग्राम मकरारा में कृषक प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भरता की दिखाई राह, बोले

उन्नत प्रजातियों से बढ़ेगा किसानों का उत्पादन

खेमराज मौर्य। शिवपुरी

विकासखंड कोलारस के ग्राम मकरारा में गत दिवस कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कृषि शक्ति योजनांतर्गत अंगीकृत यंत्रदूत ग्राम में रबी फसलों व अन्य सामयिक विषयों पर कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में योजना से जुड़े हुए किसानों के साथ ग्राम के अन्य कुल 73 कृषकों द्वारा सहभागिता की गई। प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ.एसपी सिंह एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. शैलेन्द्र सिंह कुशवाह द्वारा कृषकों को खेती की उन्नत तकनीकी की जानकारी दी गई। डॉ.एसपी सिंह द्वारा पशुओं के रखरखाव एवं संतुलित आहार प्रबंधन तथा नवजात बछड़ों/बछियों में लगने वाले अंत: परजीवी कीड़ों के नियंत्रण के लिए विभिन्न दवाओं की जानकारी दी गई।

शून्य जुताई की तकनीक भी बताई

डॉ. कुशवाह द्वारा वर्तमान रबी मौसम की फसलों एवं उनकी उन्नत किस्मों-गेहूं (आरवी डब्ल्यू 4106, एमपी 1203, राज 1555, पूसा तेजस) चना (आरवीजी 202, 203, 204) एवं सरसों (गिरिराज, आरएच 725, आरएच 749) बोने की तकनीक, संतुलित पोषण प्रबंधन, सिंचाई जल प्रबंधन एवं खरपतवार प्रबंधन की जानकारी विस्तार से दी गई। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को शून्य जुताई तकनीक के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

गांव में स्वच्छता पर फोकस

कार्यक्रम के अंत में उपयंत्री कृषि अंकित सेन द्वारा उन्नत कृषि यंत्रों में स्ट्रा रीपर, स्वचालित रीपर कम बाइंडर, जीरो टिलेज मशीन आदि के बारे में शासन की योजनाओं के साथ-साथ परिचालन संबंधी जानकारियों से कृषकों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषकों को दैनिक जीवन में मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वच्छता अपनाने पर भी बल दिया गया। स्वच्छता की आवश्यकता पर ग्रामीण परिवेश को दृष्टिगत रख उन्हें स्वच्छ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

रबी फसलों के अनुशंसित एवं संतुलित उर्वरकों का उपयोग ज्यादा लाभकारी

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केन्द्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार एवं वैज्ञानिक डॉ. यू. एस धाकड़ द्वारा रबी फसलों के विपुल उत्पादन के लिए अनुशंसित एवं सन्तुलित उर्वरकों का उपयोग ज्यादा लाभकारी है। साथ ही उत्पादन लागत को भी कम किया जा सकेगा और मृदा उर्वरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। रबी फसलों के लिए प्रति एकड़ अनुशंसित पोषक तत्वों नत्रजन, स्फुर, पोटाश की पूर्ति विभिन्न उर्वरक विकल्पों से की जा सकती है। गेहूं सिंचित के लिए प्रति एकड़ नत्रजन 40, स्फुर 24 एवं पोटाश 16 किग्रा की पूर्ति के लिए प्रथम उर्वरक विकल्प के रूप में यूरिया 87 किग्रा, सिंगल सुपर फास्फेट 150 किग्रा और म्यूरेट ऑफ पोटाश 26 किग्रा प्रति एकड़ और दूसरा उर्वरक विकल्प एनपीके (12:32:16) 75 किग्रा, यूरिया 67 किग्रा और तीसरा उर्वरक विकल्प डीएपी 50 किग्रा, यूरिया 67 किग्रा और म्यूरेट ऑफ पोटाश 26 किग्रा प्रति एकड़ और चना, मसूर एवं मटर (सिंचित) में नत्रजन 8 किग्रा, स्फुर 20 किग्रा प्रति एकड़ की पूर्ति के लिए प्रथम उर्वरक विकल्प यूरिया 17 किग्रा, सिंगल सुपर फास्फेट 125 किग्रा और दूसरा उर्वरक विकल्प के रूप में डीएपी 40-45 किग्रा प्रति एकड़ उपयोग करें और सरसों (असिंचित) मे नत्रजन 16 किग्रा, स्फुर 8 किग्रा, पोटाश 4 किग्राप्रति एकड़ पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए यूरिया 35 किग्रा, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किग्रा एवं म्यूरेट ऑफपोटाश 7 किग्रा प्रति एकड़ प्रयोग करे और सरसों (सिंचित) क्षेत्र के लिए नत्रजन 32 किग्रा, स्फुर 16 किग्रा एवं पोटाश 8 किग्रा प्रति एकड़ प्रयोग करें इन पोषक तत्वों की पूति के लिए यूरिया 70 किग्रा, सिंगल सुपर फास्फेट 100 किग्रा और म्यूरेट ऑफ पोटाश 14 किग्रा प्रति एकड़ प्रयोग करने से फसलों का अधिक उत्पादन प्राप्त होगा साथ ही कीड़े बीमारियां भी बहुत कम हानि पहुंचाएंगी।

राष्ट्रीय सीड हब योजनांतर्गत चना की नई किस्मों का बीज बिक्री के लिए उपलब्ध

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केन्द्र टीकमगढ़ में राष्ट्रीय सीड हब योजनांतर्गत चना की नई एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों आरवीजी-202, जेजी-36 एवं जेजी-12 का बीज किसानो के लिए बिक्री के लिए तैयार किया गया है। बिक्री के लिए प्रमाणित बीज की दर 7700 रुपए और आधार बीज की दर 7800 रुपए प्रति क्विंटल मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित की गयी है। किसान बीज खरीदने के लिए डॉ. एसके सिंह, वैज्ञानिक 7999344526 पर सम्पर्क कर सकते हैं। चना की उक्त सभी किस्में दस वर्ष के अन्दर की है और अधिक उत्पादन देने वाली एवं उकठा निरोधक प्रजातियां है चना की फसल मे प्रमुख समस्या उकठा रोग की रहती है, इसलिए किसानों ने चना के जगह गेहूं की खेती को ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उकठा निरोधक एवं अधिक उत्पादन वाली बहुत सी किस्में विकसित की है और इन किस्मों को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कुछ चयनित कृषि विज्ञान केन्द्रों पर उन्नत किस्म के बीजोत्पादन कार्यक्रम सीड हब में संचालित किया गया। भारत सरकार दलहन एवं तिलहन को बढ़ावा देने के

उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय तिलहन मिशन कार्यक्रम चला रही है और शासन द्वारा समर्थन मूल्य भी दलहन एवं तिलहन का अच्छा दिया जा रहा है। दलहनी फसलें लगाने से किसान को भी अच्छा लाभ होता है। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति भी अच्छी रहती है और फसलों में कीड़े बीमारी भी कम लगती है। इसलिए प्रतिवर्ष प्रत्येक खेत में फसलें अदल-बदल कर बोना चाहिए।

यूरिया, डीएपी नहीं तो वैकल्पिक उर्वरकों का किसान करें इस्तेमाल

जबलपुर। इन दिनों किसानों ने खेतों में रबी फसलों की बोवनी शुरू कर दी है। अच्छी उपज के लिए बीज तो उपलब्ध हो गया है, लेकिन खाद की कमी लगातार बनी है। किसान इसके लिए परेशान हो रहे हैं। कृषि विभाग भले ही खाद की कमी को लेकर इंकार कर रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति किसानों की परेशानी बढ़ाने वाली है। अब कृषि विभाग ने खाद की कमी को देखते हुए सलाह जारी की है, जिसमें कहा गया है कि किसान यूरिया और डीएपी की जगह वैकल्पिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल की सलाह किसानों को दी है। विभाग के मुताबिक किसान डीएपी के स्थान पर स्वास्थ्य मृदा कार्ड की अनुशंसा के आधार पर सिंगल सुपर फास्फेट, एनपीके एवं अमोनिया फास्फेट सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं यूरिया के स्थान पर इफको द्वारा तैयार किए गए नैनो तकनीक आधारित नैनो तरल यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। विभाग के अनुभवियों का मानना है कि इन उर्वरकों का उपयोग करने से जहां कृषि की लागत कम होगी वहीं गुणवत्ता और उत्पादन पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

> जिले में रबी फसलों की बोनी अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। इस समय किसान को बीज तथा उर्वरक का ध्यान देना होता है। किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी खाद, कब, किस विधि से एवं कितनी मात्रा में देना चाहिए। कृषक डीएपी एवं यूरिया का ज्यादा प्रयोग करते है। डीएपी की बढ़ती मांग एवं ऊंचे रेट से कृषकों को कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है।
> **डॉ. एसके निगम, उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, जबलपुर**

सिर्फ यूरिया डीएपी का लगातार प्रयोग मृदा स्वास्थ के लिए उपयुक्त नहीं

खेतों में रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग जरूरी

बैतूल। रबी मौसम में जिले में मुख्य रूप से गेहूं एवं चना की खेती होती हैं। इन फसलों में नत्रजन, स्फुर, पोटाश एवं जिंक की वैज्ञानिक अनुशंसा है। इन पोषक तत्वों का मृदा परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर प्रयोग उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ मृदा स्वास्थ के लिए भी आवश्यक है।

विगत कई दशक से कृषक समुदाय दो रासायनिक उर्वरक डीएपी (18:46:0) एवं यूरिया 46 प्रतिशत नत्रजन का प्रयोग लगातार कर रहा है। हमारे जिले की फसल प्रणाली में इन्हीं दो रासायनिक उवज़्रकों के प्रयोग से भूमि में पोटाष, सल्फर एवं जिंक की कमी हो रही है। इससे उत्पादन एवं गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रहे हैं। डीएपी के स्थान पर दूसरे संयुक्त काम्पलेक्स उर्वरक जैसे- एनपीके (12:32:16) या एनपीके (14:35:14) का उपयोग करने पर फसलों को महत्वपूर्ण पोषक तत्व पोटाष की पूर्ति होती है। पोटाश से फसलों की गुणवत्ता (दानों का वजन एवं चमक) बढ़ती है। साथ ही ये तत्व फसलों में कीट एवं रोग के लिए प्रतिरोधकता बढ़ाते हैं जिससे कीट व्याधि का प्रकोप कम होता है एवं फसल संरक्षण व्यय कम होता है। काम्पलेक्स उर्वरक के बदले यदि

नत्रजन के लिए यूरिया, फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट एवं पोटाष के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करने पर तीनों प्रमुख तत्वों के साथ कैल्शियम एवं सल्फ जैसे सुक्ष्म पोषक तत्व भी फसल को प्राप्त होते हैं।

उक्त पोषक तत्वों की 50 प्रतिषत पूर्तिके लिए जैव उर्वरकों जैसे दलहनी फसलों में नत्रजन के लिए राइजोबियम कल्चर, अनाज वाली फसलों में नत्रजन के लिए अजेटोबेक्टर का प्रयोग, पीएसबी कल्चर से सभी फसलों में फास्फोरस, केएसबी कल्चर से सभी फसलों में पोटाश एवं बायोफर्टिसोल कल्चर से सभी फसलों में सुक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती हैं। अत: किसानों को सलाह दी जाती है कि सिर्फ यूरिया, डीएपी का प्रयोग न करते हुए उक्त वर्णित विकल्पों में से किसी का चयन करें। जैव उर्वरकों का भरपूर प्रयोग करें। ये उर्वरक मृदा स्वास्थ एवं पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। उपरोक्त जैव उर्वरक कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल बाजार, बैतूल में उपलब्ध रहते हैं। अत: किसान जैव उर्वरक के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

-समय पर बोवनी से मिलेगा बंपर उत्पादन

गेहूं की खास किस्में, जिनमें मिलेगी अच्छी पैदावार

संवाददाता। भोपाल

गेहूं की खेती में अगर उन्नत किस्मों का चयन किया जाए, और समय से बोवनी की जाए तो फसल का बंपर उत्पादन मिलना तय है। रबी की फसल की बोवनी का समय आ गया है ऐसे में किसानों के लिए नई किस्मों की जानकारी जरूरी है। गेहूं की कुछ नई किस्मों का विकास वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जिनका परिणाम बहुत अच्छा देखने को मिला है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन किस्मों की समय से बोवनी कर किसान अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।

एचआई-8663

इस किस्म से उच्च गुणवत्ता व ज्यादा उत्पादन मिलेगा। यह किस्म गर्मी को सह सकती है। इससे 120-130 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है और उपज 50-55 क्विंटल मिलती है।

पूसा तेजस

गेहूं की नई किस्म पूसा तेजस को मध्य भारत के लिए चिह्नित किया गया है। यह किस्म 3 से 4 सिंचाई में पककर तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर 55-75 क्विंटल उपज देती है। इस गेहूं से चपाती के साथ पास्ता, नूडल्स और मैकरॉनी जैसे खाद्य पदार्थ भी बनाए जा सकते हैं। इस किस्म में प्रोटीन, विटामिन-ए, आयरन व जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं।

पूसा उजाला

पूसा उजाला कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। 1 से 2 सिंचाई में फसल पककर तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर 30 से 44 क्विंटल उपज मिल सकती है। इस किस्म के गेहूं में प्रोटीन, आयरन और जिंक की अच्छी मात्रा होती है।

जे-डब्ल्यू 3336

इस किस्म को न्यूट्रीफार्म योजना के तहत विकसित किया गया है। इसमें जिंक प्रचुर मात्रा में होता है और यह 2 से 3 सिंचाई में फसल तैयार कर देती है। यानि इस किस्म से 110 दिन में फसल तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर 50-60 क्विंटल उपज मिल जाती है।

जीवामृत के फायदे और जीवामृत बनाने की विधि

फसलों के लिए अमृत जीवामृत

संवाददाता। भोपाल।

जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है। जिसे गोबर के साथ पानी में कई और पदार्थ जैसे गौमूत्र, बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी, गुड़ और दाल का आटा मिलाकर तैयार किया जाता है। जीवामृत पौधों की वृद्धि और विकास के साथ साथ मिट्टी की संरचना सुधारने में काफी मदद करता है। यह पौधों की विभिन्न रोगाणुओं से सुरक्षा करता है। पौधों की प्रतिरक्षा क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे पौधे स्वस्थ बने रहते हैं। फसल से बहुत ही अच्छी पैदावार मिलती है। फसल को दी जाने वाली प्रत्येक सिंचाई के साथ 200 लीटर जीवामृत का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से उपयोग किया जा सकता है, अथवा इसे अच्छी तरह से छानकर टपक या छिड़काव सिंचाई के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त होता है। छिड़काव के लिए 10 से 20 लीटर तरल जीवामृत को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है।

तरल जीवमृत बनाने की सामग्री

- -प्लास्टिक का एक ड्रम (लगभग 200 लीटर)
- -10 किलो देशी गाय का गोबर
- -10 लीटर पुराना गौमूत्र
- -1 किलो गुड या 4 लीटर गन्ने का रस
- -1 किलो बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी
- -1 किलो दाल का आटा
- -1 ढकने का कपड़ा

तरल जीवामृत बनाने की विधि

सबसे पहले एक प्लास्टिक बड़ा ड्रम लिया जाता है जिसे छायां में रखकर दिया जाता है। इसके बाद 10 किलो देशी गाय का ताजा गोबर, 10 लीटर पुराना गोमूत्र, 1 किलोग्राम किसी भी दाल का आटा (अरहर, चना, मूंग, उड़द आदि का आटा), 1 किलो बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी तथा 1 किलो पुराना सड़ा हुआ गुड़ को 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से लकड़ी की सहायता से मिलाया जाता है। अच्छी तरह मिलाने के बाद इस ड्रम को कपड़े से इसका मुंह ढक दें। इस घोल पर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। अगले दिन भी इस घोल को फिर से किसी लकड़ी की सहायता से दिन में दो या तीन बार हिलाया जाता है। लगभग 5-6 दिनों तक प्रतिदिन इसी कार्य को करते रहना चाहिए। लगभग 6-7 दिन के बाद, जब घोल में बुलबुले उठने कम हो जाये तब समझ लेना चाहिए कि जीवामृत तैयार हो चुका है। जीवामृत का बनकर तैयार होना ताप पर भी निर्भर करता है अत: सर्दी में थोड़ा ज्यादा समय लगता है किन्तु गर्मी में 2 दिन पहले तैयार हो जाता हो जाता है। यह 200 लीटर जीवामृत एक एकड़ भूमि के लिए सिंचाई के साथ देने के लिए पर्याप्त है।

जलकुंभी से तैयार कम्पोस्ट खाद पौधों के लिए जीवनदायनी

जैविक खेती कृषि के लिए वरदान

भोपाल। जलकुंभी पांटीडेरीयेसी कुल का स्वतंत्र रूप से जल में तैरने वाला खरपतवार है। इसके पौधे ऊंचाई में कुछ सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं। इसका तना खोंखला और छिद्रदार होता है। पर्व संधियों से झुंड में रेशेदार जड़ें निकलती है। इसकी पत्तियां चिकने हरे रंग की होती है। इस पौधे के फूल नीले, सफेद-बैंगनी रंग के आकर्षक होते हैं। इन पौधों की पत्तियों में हवा भरी होती है जिससे ये जल की सतह पर आसानी से तैर सकते हैं। इसके बीज लंबे समय तक जीवित रहते हैं। यह खरपतवार बहुत तेजी से प्रगुणन और वृद्धि करता है और लगभग 12-15 दिन में इसकी संख्या दोगुनी हो जाती है।

जलकुंभी के फायदे- जलकुंभी के दुष्प्रभावों के साथ-साथ इसमें बहुत से आर्थिक गुण भी पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पौधे का उपयोग जैव-गैस संयंत्रों में कच्चे पदार्थ के रूप में किया जा सकता है। जलकुंभी पौधे का उपयोग कम्पोस्ट बनाकर कमाई का जरिया बनाया जा सकता है। जलकुंभी से तैयार कम्पोस्ट को गृह वाटिका में सब्जियों, फलों और सजावटी पौधों को उगाने में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जलकुंभी कम्पोस्ट को नर्सरी में पौधों को तैयार करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

हरी खाद के रूप में उपयोग

कम्पोस्ट को जमीन से निकाली गई पौध की जड़ों की नमीं को बनाए रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जलकुंभी का उपयोग पौध प्रसारण विधियों जैसे दाव कलम (लेयरिंग) तथा रोपण (ग्राफ्टिंग) में भी किया जा सकता है। जलकुंभी में 96प्रतिशत जल, 0.04प्रतिशत नाइट्रोजन, 0.0.6प्रतिशत फॉस्फोरस, 0.2 प्रतिशत पोटैशियम, 3.5 प्रतिशत कार्बनिक तत्व और 1 प्रतिशत लौह तत्व के अलावा अनेक प्रकार के एमिनो अम्ल भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते है। अत: पौधे को हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

अन्नदाता जाने बनाने की विधियां और उसके फायदे

घर में बन जाएगी कम्पोस्ट खाद, किसान होंगे आत्मनिर्भर

संवाददाता। भोपाल

कम्पोस्ट को 'कूड़ा खाद' कहते हैं। पौधों के अवशेष पदार्थ, घर का कूड़ा कचरा, मनुष्य का मल, पशुओं का गोबर आदि का जीवाणु द्वारा विशेष परिस्थिति में विच्छेदन होने से यह खाद बनती है। अच्छा कम्पोस्ट खाद गंद रहित भूरे या भूरे काले रंग का भुरभुरा पदार्थ होता है। इसके 0.5 से 1.0 प्रतिशत पोटाश एवं अन्य गौण पोषक तत्व होते हैं। कम्पोस्ट खाद बनाने की कई आसान विधियां प्रचलन में हैं, जो इस प्रकार हैं।

गड्ढा विधि: ऊंची जगह पर जहां पानी भी पास में एक गड्ढा बना लें। गड्ढे का आकार 3 मीटर लम्बा, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा रखें। खोदने के बाद गड्ढे को गोबर से लीप दें। इसके बाद पोषक तत्वों को सोखने के लिए 10 से 12 सेमी की सेंद्रीय पदार्थों की आधार परत बिछाएं। इस आधार परत पर 20 सेमी मोटी पहली परत गौशाला की बिछावन डालें, गोबर एवं गोबर से सना हुआ पुआल गन्ने का छिलका, अन्य कचरा तथा पत्तियां बिछाएं। 50 प्रतिशत गोबर एवं गौमूत्र का पानी सोखने की क्षमता का उपयोग हो सके। अब 100 किग्रा भुरभुरी मिट्टी में 3 किग्रा अधपका गोबर कम्पोस्ट तथा 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट या 3-5 किग्रा राक फॉस्फेट मिलाकर मिश्रण बनाएं। इस मिश्रण की 2-3 सेमी परत बिछाएं और पानी से गीला कर दें। इन परतों की पुनरावृत्ति जब तक करते रहें, तब तक गड्ढे की पूरी सामग्री अच्छी तरह हिलाते हुए पलटें।

ढेर विधि: इस विधि में कम्पोस्ट बनाने के लिए जमीन के ऊपर कोठी बनाते हैं। ऊंची व समतल भूमि पर 3 मीटर लम्बी, 2 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची कोठी, अनुपयोगी लकड़ी की पट्टियां, चटाइयां एवं ईंटों से बनाई जा सकती है। 2 सेमी ईंटों की तह जमा देने से ढेर लगाने में सुविधा होती है। इस विधि में भी भरने का तरीका गड्ढा विधि जैसे ही है, लेकिन इस विधि में गोबर के घोल की अधिक आवश्यकता होती है। ऊपर का हिस्सा ढाल देते हुए भरें तथा मिट्टी, भूसे के मिश्रण के 5 सेमी प्लास्टर कर गोबर से लीप दें। हर 4-6 सप्ताह में खाद को पलटते रहें और नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करते रहें और पुन: लीप कर बन्द कर दें इस प्रकार 3 माह में कम्पोस्ट बनकर तैयार हो जाता है।

कम्पोस्ट खाद के लाभ

1. यह सस्ता है, क्योंकी यह फसल के अवशेषों, गोबर, घास और अन्य घरेलू कचरे से बनती है। पौधे इसके पोषक तत्वों को अधिक दुटने की बजाय सीधे ग्रहण कर लेते हैं। इससे फसल की पैदावार में तुरंत प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है जिससे फसल को समर्थन मिलता है और पानी की बचत होती है। भूमि की पोषण शक्ति प्रभावित नहीं होती है।

अफसर गांवों की आवश्यकताओं के अनुरूप लें संकल्प और उन्हें समय पर करें पूरा

छह राज्यों की कार्यशाला में बोले केंद्रीय पंचायती राज के सचिव

जीवंत हों ग्राम सभाएं

सबकी योजना-सबका विकास जन-अभियान पर हुआ मंथन

प्रशासनिक संवाददाता। भोपाल

ग्रामों के सतत संवहनीय एवं समावेशी विकास के लिए उनका वाइब्रेंट (जीवंत) होना आवश्यक है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस संबंध में पहल की है। हर ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत के विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित संवहनीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह बात केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने सबकी योजना-सबका विकास जन-अभियान वर्ष 2021-22 में मप्र सहित 6 राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों की दो-दिवसीय कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कही। कार्यशाला का आयोजन प्रशासन अकादमी, भोपाल में केंद्रीय, पंचायती राज मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, हैदराबाद द्वारा किया गया था।

गांव में पहले तय करें काम

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजना बनाने के दौरान संकल्प लें कि वे अपने गांवों में कौन-कौन से कार्य करना चाहती हैं। साथ ही गत वर्ष लिए गए संकल्पों की पूर्ति की समीक्षा करें। विभिन्न शासकीय विभाग योजनाओं का क्रियान्वयन करें तथा ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों की मॉनिटरिंग हो।

अधिकारियों की नहीं दिख रही रुचि

सुनील कुमार ने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारी ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का समुचित प्रस्तुतिकरण दें। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि गत 2 अक्टूबर से देश में 14 हजार ग्राम सभाएं आयोजित की गईं, उनमें अधिकारियों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं थी। केवल 42 फीसदी ग्राम सभाओं में ही कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए। इस संबंध में राज्य सरकारों को पत्र भी लिखा जा रहा है।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल

केंद्र सरकार द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इस पर शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी संक्षिप्त रूप में दर्ज की जा रही है। कार्यशाला में मप्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की गई सहभागी ग्राम विकास नियोजन प्रक्रिया के संबंध में ट्रेनिंग मैन्युअल का विमोचन एवं ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधी लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

यह रहे मौजूद

शुभारंभ-सत्र में भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव रेखा यादव, एनआईआरडीपीआर हैदराबाद के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. केथेरिसन, संचालक पंचायत आलोक कुमार सिंह उपस्थित थे। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थानों को सौंपे गए 29 विषयों के संबंध में 18 लियन विभागों के मप्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, यूपी, हरियाणा और बिहार राज्यों के अधिकारी व पंचायत पदाधिकारी शामिल हुए।

किसानों को बेहद कम कीमत पर नैनो डीएपी खाद मिलेगा

» नैनो डीएपी की उर्वरक उपयोग दक्षता 72 फीसदी से ज्यादा

» इफ्को द्वारा शुरू हुआ ट्रायल अब अंतिम दौर में पहुंचा

यूरिया के बाद नैनो डीएपी कम करेगी खेती का खर्च

भोपाल। मोदी सरकार किसानों को अब नैनो यूरिया के बाद तरल नैनो डीएपी खाद भी बोतल में देने जा रही है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निर्देश पर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को द्वारा शुरू हुआ ट्रायल अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। इफ्को ने जो नैनो डीएपी विकसित किया है, उसकी उर्वरक इस्तेमाल दक्षता 72 फीसदी से अधिक है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया नैनो डीएपी के ट्रायल के बारे में लगातार इफ्को से जानकारी ले रहे हैं। बहुत जल्द ही ट्रायल का काम पूरा हो जाएगा। अभी तक के ट्रायल के जो नतीजे आए हैं, वह काफी उत्साहजनक हैं। नैनो डीएपी के बाजार में आ जाने के बाद केंद्र सरकार को लाखों करोड़ रुपए की बचत तो होगी ही, साथ ही किसानों को बेहद ही कम कीमत पर नैनो डीएपी खाद मिलेगा।

किसानों को 848 रुपए का होगा फायदा- नैनो डीएपी का आकार 10 से 30 नैनो मीटर है। इफ्को के मुताबिक, एक एकड़ जमीन में जितनी पारंपरिक डीएपी डाली जाती है, उसके मुकाबले इतनी ही जमीन में नैनो डीएपी की बहुत कम जरूरत होगी। धान की फसल पर एक एकड़ जमीन में 52 किलो पारंपरिक डीएपी का इस्तेमाल करना होता है। इसकी कुल कीमत 2508 रुपए है। इसमें से 1,248 रुपए किसान को देना होता है और 1260 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। जबकि, इतनी ही जमीन पर धान की फसल के लिए सिर्फ आधे लीटर नैनो डीएपी के इस्तेमाल की जरूरत होगी। इसके लिए किसानों को सिर्फ 400 रुपए खर्च करने होंगे। यानी किसानों को 848 रुपए का सीधा फायदा होगा।

नौनो 90 फीसदी फसल में समाहित

वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए इफ्को चंडीगढ़ के डीजीएम ओंकार सिंह ने बताया कि नई फसलों की बोवनी का समय शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि अभी हम जो डीएपी फसल में डालते हैं उसका 80 प्रतिशत जमीन में बर्बाद हो जाता है। जबकि नया नैनो डीएपी तरल रूप में आता है और यह 90 प्रतिशत तक फसल में समा जाता है। जिससे फसल को ज्यादा फायदा होता है।

ट्रायल कर रहे इफ्को के विशेषज्ञ

किसानों को अब जल्दी ही डीएपी खाद भी आधा लीटर की बोतल में मिलने लगेगा। तरल नैनो यूरिया के बाद इफ्को ने तरल नैनो डीएपी भी बाजार में उतारने की तैयारी कर ली है। फिलहाल इफ्को के विशेषज्ञ हरिद्वार जिले के पांच गांवों में धान की फसल पर तरल नैनो डीएपी के प्रभाव का ट्रायल करने में जुटे हैं। अभी तक किसानों को यूरिया व डीएपी 45 किलो व 50 किलो के बोरे में मिलता है। हाल ही में इफ्को ने तरल नैनो यूरिया इजाद किया है। सफल ट्रायल के बाद अब इसका उत्पादन शुरू हो गया है। इफ्को ने तरल नैनो डीएपी भी तैयार किया है। इफ्को के एसएफए ओमवीर सिंह ने बताया कि नैनो यूरिया की तरह ही 500 एमएल की बोतल में आने वाला नैनो डीएपी भी पानी में मिलाकर फसल में स्प्रे किया जाएगा। इफ्को के जिला प्रबंधक डॉ. रामभजन सिंह ने बताया कि हरिद्वार के लाठरदेवा हूण, लिब्बरहेड़ी, जसवावाला, सोहलपुर व नगला एमाद गांव में 10 किसानों के खेत में धान की फसल पर फिलहाल नैनो डीएपी का ट्रायल किया जा रहा है।

नैनो जिंक और कापॅर भी आयेगा

इफ्को जल्द ही कृषि लागत में कमी के उद्देश्य से नैनो जिंक और नैनो कापॅर बाजार में उतारने वाला है, जिसकी घोषणा विगत दिनों इफ्को के प्रबंध निदेशक उदय शंकर अवस्थी ने राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए की।

-कचरिया की कीमत वही जानता है जिसने इसका स्वाद चखा

बालाघाट में भी हो रही औषधीय फलदार सब्जी

रफी अहमद अंसारी। बालाघाट

यूं तो सभी सब्जियां अपने स्वाद और गुणों को लेकर आज भी शोध का विषय बनी हुई हैं। इन्हें इनकी खूबियों ने ही बचाए रखा है। ऐसी ही एक फलदार सब्जी है कचरिया इसे जानने वाले अलग-अलग तरह से इसका सेवन करते हैं। यह फल जरूर एक है। लेकिन इसके फायदे अनेक है। यह भूख बढ़ाने में टॉनिक को भी मात देती है। इसके साथ ही कब्ज के लिए रामबाण है। सर्दी-जुकाम की इससे अच्छी कोई औषधि नहीं है। इसकी गरम तासीर ठंड से होने वाली कई बीमारियों को जड़ से मिटा देती है। इसकी तासीर गर्म होती है जो सर्दी जुकाम के लिए बेहद फायदेमंद होती है। अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। कोरोना काल में भी यह जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए सहारा बनी है। कोरोना से आयुर्वेद पद्धति से लड़ने वालों के लिए कचरिया भी खास पसंद रही है।

कचरिया बढ़ाती है भूंख

पातालकोट रसोई का प्रतिनिधित्व कर रहे पवन श्रीवास्तव बताते हैं कि पारंपरिक व्यंजनों की उनकी रसोई में कद्दू की खीर, मक्के रोटी के साथ महुए की पूड़ी, भेदरा टमाटर की चटनी के साथ बरबरटी की दाल के बड़े भी खास हैं। उससे भी ज्यादा खास है औषधीय गुणों से भरपूर कचरिया, यह कच्ची होती है तो इसमें कड़वाहट होती है, लेकिन सुखाकर खाने से इसमें मौजूद पोषक तत्व इसमें सौंधापन लाते हैं। बीमारी में अगर मुंह का स्वाद बिगड़ जाए तो टेस्ट बदलने के साथ ही भूख भी बढ़ाती है। कचरिया इन दिनों आदि रंग उत्सव के बाजार में पातालकोट की रसोई के व्यंजनों में शामिल यह सब्जी पारंपरिक व्यंजनों के बीच खास है।

विकास के पथ पर अग्रसर होगा कृषि क्षेत्र, किसानों की आय दोगुनी करने में मिलेगी मदद

कृषि-उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव

कृषि-उपज को मिली 'उड़ान'

विशेष संवाददाता। भोपाल

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कृषि उड़ान 2.0 का शुभारंभ किया। कृषि उड़ान 2.0 का उद्देश्य कृषि-उपज और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण और अनुकूलन के माध्यम से मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने और विभिन्न और गतिशील परिस्थितियों में कृषि-मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन लाने में योगदान देना है। इस योजना में हवाई परिवहन द्वारा कृषि-उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।

कृषि क्षेत्र में खुलेंगे विकास के नए द्वार: इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, कृषि उड़ान 2.0 नीति निर्माण के प्रति इस सरकार के सहयोगात्मक दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। यह योजना कृषि क्षेत्र के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगी और कृषि उपज की आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक और उसके परिवहन में आने वाली बाधाओं को दूर करके किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि हम ए-2-ए- कृषि से विमानन के मॉडल को अपनाकर अन्नदाता को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं।

किसे होगा फायदा

कृषि उड़ान 2.0 को देश भर के 53 हवाई अड्डों पर मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाएगा। इससे किसान, मालवाहकों और एयरलाइन कंपनियों को लाभ होने की संभावना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय पहले छह महीने के लिए प्रायोगिक आधार पर इस योजना को लागू करने की योजना बना रहा है और फिर अन्य हितधारकों के साथ इसके मूल्यांकन और परामर्श के परिणामों के आधार पर इसमें संबंधित संशोधन किया जाएगा।

प्रस्तावित समयावधि

अगरतला, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, दीमापुर, हुबली, इम्फाल, जोरहाट, लीलाबारी, लखनऊ, सिलचर, तेजपुर, तिरुपति और तूतीकोरिन रूट के लिए वर्ष 2021-2022 तक प्रस्तावित है, जबकि अहमदाबाद, भावनगर, झारसुगुडा, कोझीकोड, मैसुरु, पुडुचेरी, राजकोट और विजयवाड़ा रूट का काम वर्ष 2022-2023 तक पूरा हो जायेगा। आगरा, दरभंगा, गया, ग्वालियर, पाकयोंग, पंतनगर, शिलांग, शिमला, उदयपुर और वडोदरा रूट के लिए वर्ष 2023-2024 तक, जबकि होलंगी और सेलम रूट का कार्य वर्ष 2024-2025 तक पूरा होने की संभावना है।

कृषि उड़ान 2.0 की मुख्य विशेषताएं

- हवाई परिवहन द्वारा कृषि-उत्पादों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना और उसे प्रोत्साहित करना
- हब और स्पोक मॉडल और फ्रेट ग्रिड (कार्गो टर्मिनलों के लिए चिन्हित स्थान) के विकास को सुगम बनाना
- कनवर्जेन्स तंत्र की स्थापना के माध्यम से संसाधन पूलिंग
- हवाई अड्डों के भीतर और हवाई अड्डों के बाहर माल ढुलाई से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
- ई-कुशल (सतत समग्र कृषि-रसद के लिए कृषि उड़ान) का विकास
- तकनीकी कनवर्जेन्स

यह रहे मौजूद

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ एमओसीए की संयुक्त सचिव ऊषा पाधी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव, आईक्लास के सीईओ और फिक्की के महासचिव मौजूद थे।

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विवि में प्रत्यारोपण अनुसंधान में मिली बड़ी सफलता

मध्यप्रदेश में पहली बार भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोग से देशी गाय ने दी जुड़वां साहीवाल बछिया

प्रवीन नामदेव। जबलपुर

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विवि में देशी गाय में भ्रूण प्रत्यारोपण को लेकर चल रहे अनुसंधान में बड़ी सफलता मिली है। विवि के पशु विज्ञानियों द्वारा दूध न देने वाली देशी गायों में आधुनिक तकनीक से भ्रूण प्रत्यारोपण किया, जिससे देशी गाय ने दो जुड़वा साहीवाल बछिया को जन्म दिया है। विवि का दावा है कि इस तरह का अनुसंधान मप्र में पहली बार सफल हुआ है। विवि के कुलपति प्रो. एसपी तिवारी ने बताया कि निकट भविष्य में गौ-वंश के नस्ल सुधार इसी तकनीक के माध्यम से किया जाएगा, जिससे उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गायों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। विवि द्वारा किए जा रहे अनुसंधान की सफलता को लेकर लगातार समीक्षा की गई, जिसका यह परिणाम रहा कि वेटरनरी विवि के वैज्ञानिकों को पहली बार में ही इसमें सफलता हासिल की।

तकनीक सिद्ध होगी वरदान- इस तकनीक के

माध्यम से अब दूध न देने वाली देशी गायों से उच्च कोटि की गुणवत्ता गायों को जन्म दिया जा सकेगा। पशुपालकों के लिए यह तकनीक अब वरदान सिद्ध होगी। इस कार्य को डॉ. एपी सिंह और उनके साथ नितिन बजाज व डॉ. अभिषेक बिसेन के साथ डॉ. सुनील कुमार बाजपेयी उपसंचालक, डॉ. विष्णु गुप्ता, सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ एवं सहयोगियों पशुपालन एवं डेयरी विभाग का सहयोग रहा।

इस तकनीक का मध्यप्रदेश में प्रथम प्रयोग इस विवि. के वैज्ञानिकों ने 9 माह पूर्व, 28 जनवरी 2021 को किया था, जिसमें गाय में भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया था। इसमें देशी गाय में दो साहीवाल भ्रूणों का प्रत्यारोपित किया गया था, जिसके बाद गाय ने जुड़वां साहीवाल बछिया को जन्म दिया। मंगलवार की सुबह भी एक और देशी गाय ने भी एक बछिया और एक बछड़े को जन्म दिया।

प्रो. एसपी तिवारी, कुलपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विवि, जबलपुर

अभी यह सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं है। इसमें सबसे जरूरी यह है कि जिला या संभाग स्तर पर स्थापित पशु चिकित्सा केंद्रों में आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ होना जरूरी है। जैसे अभी किसी को रीवा में अपनी गाय में भ्रूण प्रत्यारोपण कराना हो तो हम वहां नहीं जा पाएंगे। न ही संबंधित अपनी गाय लेकर यहां आ पाएंगे।

डॉ. एके गौर, पीआरओ, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विवि, जबलपुर

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)